NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE

किसान उत्पादक संगठन: कृषक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक

कृष्णा यादव[1], श्याम जी[2]

परिचय:

FPO, किसान-उत्पादकों का एक संगठन है जो इनपुट, तकनीकी सेवाओं से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक खेती के लगभग सभी पहलुओं को कवर करने वाली एंड-टू-एंड सेवाओं के साथ छोटे किसानों को सहायता प्रदान करता है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सदस्यता के सिद्धांत के आधार पर एक साथ आने वाले किसानों के समूह हैं, जो विशिष्ट सामान्य लक्ष्य का पीछा करते हैं और खेती को आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित करते हैं जो उनके सदस्यों को लाभान्वित करते हैं और उनके साथ काम करने वाले भागीदारों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। एक उत्पादक संगठन (पीओ) प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है जिसमे किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार आदि होते हैं। यह किसानों का, किसानों द्वारा और किसानों के लिए संगठन है। एफपीओ एक या एक से अधिक संस्थानों, लोगों या संगठनों द्वारा संघटन, पंजीकरण, व्यापार रणनीति और संचालन में सहायता के माध्यम से प्रायोजित किया गया हो सकता है। हालाँकि, प्रबंधन सदस्य प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, और स्वामित्व नियंत्रण हमेशा सदस्यों के पास होता है।

किसान उत्पादक संगठन का उद्देश्य:

- एफपीओ का मुख्य उद्देश्य अपने स्वयं के संगठन के माध्यम से उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना है।
- इसके अलावा, कृषि विपणन में, बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला होती है जो अक्सर गैर-पारदर्शी तरीके से काम करते हैं जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां उत्पादक को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए मूल्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त होता है। इसका सफाया किया जाएगा।

एफपीओ की महत्वपूर्ण गतिविधि:

1. बाजार की जानकारी, प्रौद्योगिकी और नए विचार का प्रसार करना, 2. इनपुट के लिए वित्त पोषण की सुविधा। 3. उपज का एकत्रीकरण और भंडारण। 4. सुखाने, सफाई और ग्रेडिंग। 5. ब्रांड निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग और मानकीकरण।

एफपीओ की स्थापना के चरण:

1. ग्राम समुदाय को समझना
2. समाज में संभावित नेताओं की पहचान करना।
3. चिन्हित नेताओं से बात करना और अन्य एजेंसियों से सहयोग मांगना
4. सामुदायिक नेताओं को समाज की

कृष्णा यादव[1], श्याम जी[2]

[1](स्नातक छात्र), एलीट कॉलेज ऑफ हाइयर एजुकेशन, उतमानपुर, बांगरमऊ, उन्नाव

[2](परास्नातक छात्र), कृषि प्रसार विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या

बैठकें बुलाने के लिए मदद करना

5. एफपीओ विकसित करने के लिए मध्य समूह के नेताओं को नामित करना
6. एफपीओ के लिए एक संगठनात्मक संरचना और प्रबंधन का विकास करना
7. कार्रवाई के लिए समूहों को प्रेरित करना
8. चयनित कार्यक्रमों को लागू करना
9. निगरानी और प्रगति के मूल्यांकन के माध्यम से नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

एफपीओ के लाभ:

एफपीओ ऊपर सूचीबद्ध किसी भी/कई/सभी गतिविधियों को करके सदस्यों को अधिक आय प्राप्त करने में सहायता करेगा। इनपुट की मांग को जोड़कर, एफपीओ थोक में खरीदारी कर सकता है, इस प्रकार व्यक्तिगत खरीद की तुलना में सस्ती कीमत पर खरीदारी कर सकता है। इसके अलावा, थोक में परिवहन करने से परिवहन की लागत कम हो जाती है। इसी तरह, एफपीओ सभी सदस्यों की उपज को एकत्र कर सकता है और थोक में बाजार बना सकता है, इस प्रकार, उपज की प्रति यूनिट बेहतर कीमत प्राप्त कर सकता है। एफपीओ उत्पादकों को बाजार की जानकारी भी प्रदान कर सकता है ताकि वे बाजार मूल्य अनुकूल होने तक अपनी उपज को रोक सकें। इन सभी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप किसानों को अधिक आय होगी।

किसान उत्पादक संगठन को सरकार का समर्थन:

सरकार ने अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नए एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्ध संसाधनों के साथ "कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" नामक एक नई समर्पित केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। प्रत्येक एफपीओ के लिए समर्थन उसके स्थापना के वर्ष से 5 वर्षों तक जारी है। भारत सरकार ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान दस हजार नए एफपीओ के गठन को मंजूरी दी है और इन संगठनों को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ रुपये दिए हैं। ये एफपीओ भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगे। मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत एफपीओ में कम से कम 300 किसान सदस्य के रूप में होने चाहिए ताकि ऊपर दी गई धनराशि का लाभ मिल सके। इसी तरह, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।

प्रारंभ में, एफपीओ बनाने और बढ़ावा देने के लिए तीन कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी,

1. छोटे किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)
2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)
3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
4. राज्य भी यदि चाहें तो डीएसीएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से अपनी कार्यान्वयन एजेंसी को नामित कर सकते हैं।